awarded to the French Consortium, led by M/s. CGEE Alsthom (now known as CEGELEC), as its offer was lower in the net cost.

(e) As per the terms of the contract with the French Consortium, the project is expected to be completed within 57 months, i.e. by July, 1994, and no delay is envisaged at this stage.

(f) There is no cost escalation or time over-run on the project, sanctioned in 1989.

वायुदूत के डोरनियर विमान में सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करना

*145. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के डोरनियर विमानों में सुरक्षा मानदंड और रख-रखाव प्रणाली में सुधार के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त समिति द्वारा सुझाये गये विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां ।

ख) प्रश्न नहीं है ।

(ग) सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और इसमें सुझाये गये सुरक्षा उपायों का वायुदूत लिमिटेड द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पेट्रोल की खपत

*146. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या पेट्रोलियम और सायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने पेट्रोल का प्रतिवर्ष उपभोग हो रहा है और उसमें से कितने पेट्रोल की खपत केन्द्र और राज्यों में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होती है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोल की खपत का प्रतिशत कितना है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल के उपभोग में कटौती के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार सरकारी अधिकारियों से सरकारी गाड़ियां वापस लेकर उसके स्थान पर कुछ भत्ता देने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस०गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में पेट्रोल की कुल खपत 3.48 मिलियन टन थी । केन्द्र और राज्यों के सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा पेट्रोल की खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) सभी सरकारी एजेंसियों और विभागों को सलाह दी गई है कि वे वर्ष 1989-90 की पेट्रोल और डीजल की खपत की तुलना में सरकारी वाहनों में 20% की कटौती करें । सरकारी वाहनों को वापस लेने और उसके बदले में सरकारी अधिकारियों को कुछ भत्ता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

Plan to Modernise Airports

*147. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express of the 10th July, 1990